Contemporaneity of Language and Literature in the Robotized Millennium

Vol: 8(1), 2026

REST Publisher; ISBN: 978-81-936097-3-6

Website: https://restpublisher.com/book-series/cllrm/

DOI: https://doi.org/10.46632/cllrm/8/1/10

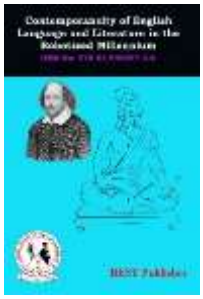

Factors Influencing India–ASEAN Relations: Political, Economic, Cultural, and Institutional Dimensions

***Bindiya Tak, Pratibha Sharma**

MVS College, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed-to-be University), Udaipur, Rajasthan, India.

*Corresponding author Email: drkiransoni77@gmail.com

अमूर्त: *1990* के दशक की शुरुआत से भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ *(*आसियान*)* के बीच आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक हितों से प्रेरित होकर संबंध काफ़ी गहरे हुए हैं। हालाँकि, कई कारक इस रिश्ते को आकार देते हैं और कभी-कभी इसे चुनौती भी देते हैं। यह लेख भारत-आसियान संबंधों को प्रभावित करने वाले बहुआयामी कारकों की जाँच करता है। हम राजनीतिक और सुरक्षा गतिशीलता *(*परमाणु प्रसार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भिन्न नीतिगत विचारों सहित*)*, आर्थिक पूरकताओं और व्यापार संभावनाओं, साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, साथ ही संस्थागत और मानक मतभेदों *(*जैसे, आसियान की आम सहमति और अहस्तक्षेप की नीति*)* के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। हम यह भी विचार करते हैं कि व्यापक भू-राजनीतिक बदलाव - उदाहरण के लिए, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और चीन का उदय - साझेदारी को कैसे प्रभावित करते हैं। हाल के शोध और नीति विश्लेषणों की समीक्षा करके, हम यह पहचानते हैं कि पारस्परिक आर्थिक हित और रणनीतिक अभिसरण आम तौर पर घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करते हैं, जबकि संस्थागत विशिष्टताएँ और भिन्न खतरे की धारणाएँ *(*जैसे, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर भारत का सतर्क रुख*)* चुनौतियाँ पेश करती हैं। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि मतभेदों के बावजूद, दोनों पक्षों के पास संघर्षों को हल करने के लिए प्रोत्साहन हैं, और भारत-आसियान संबंधों के साझा क्षेत्रीय पहलों और समुदाय-निर्माण प्रयासों के ढांचे के तहत बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्य शब्द: भारत-आसियान संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, राजनीतिक-सुरक्षा कारक, आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक कूटनीति, आसियान मार्ग, एक्ट ईस्ट नीति।

1. परिचय

1990 के दशक की शुरुआत से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को प्रमुखता मिली है। अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी (जिसे बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया) के तहत, नई दिल्ली ने एक ब्लॉक के रूप में आसियान और उसके सदस्य राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की मांग की है। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है, "जैसा कि भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, आसियान एक (संभावित) साझेदार और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के इच्छित आउटरीच के एक अनिवार्य घटक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है" (किपगेन, 2020)। इस नीति की 2000 और 2010 के दशक में फिर से पुष्टि की गई, जो

एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण और क्षेत्रीय गतिशीलता को संतुलित करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य को दर्शाती है। 1967 में स्थापित आसियान स्वयं एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है 1990 के दशक में भारत का आर्थिक उदारीकरण आसियान के विकास के साथ-साथ हुआ, जिससे व्यापार और निवेश में पारस्परिक रुचि पैदा हुई। 2000 के दशक के आरंभ में आसियान-भारत शिखर-स्तरीय साझेदारी के समय तक, द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार वस्तुओं (2009) और सेवाओं/इलेक्ट्रॉनिक्स (2014) में मुक्त व्यापार समझौते को शामिल करने तक हो चुका था।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, भारत-आसियान संबंधों के अध्ययन का महत्व स्पष्ट है: आसियान भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों में से एक है और उभरती एशिया-प्रशांत व्यवस्था में एक रणनीतिक स्थान है। उनके संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आर्थिक नीति, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय संरचना के लिए निहितार्थ रखता है। आसियान के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में "आसियान केंद्रीयता" की उसकी खोज को भी दर्शाता है। जैसा कि इंडिया रिव्यू में संक्षेप में कहा गया है, भारत-आसियान संबंध अब राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक/सांस्कृतिक आयामों तक फैले हुए हैं (योंग और मुन, 2009)। यह लेख इन आयामों का विश्लेषण करता है, सहयोग के प्रेरकों (जैसे पूरक अर्थव्यवस्थाएँ और साझा सांस्कृतिक विरासत) और टकराव के बिंदुओं (जैसे संस्थागत मतभेद और बाहरी सुरक्षा खतरे) की पहचान करता है।

2. अनुसंधान के उद्देश्य

1. भारत-आसियान संबंधों को आकार देने वाले राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों की जांच करना।
2. भारत-आसियान संबंधों पर बाहरी प्रभावों और हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण करना।

3. अनुसंधान का महत्व

भारत-आसियान संबंधों को समझना नीतिगत और शैक्षणिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। नीति निर्माताओं के लिए, आसियान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत दक्षिण पूर्व एशिया को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनाता है (किपगेन, 2020)। इस संबंध को प्रभावित करने वाले कारकों की अंतर्दृष्टि व्यापार सौदों पर बातचीत करने से लेकर सुरक्षा अभ्यासों के समन्वय तक, कूटनीतिक रणनीति को सूचित करती है। विद्वानों के लिए, भारत-आसियान संबंध एक क्षेत्रीय साझेदारी का एक सम्मोहक मामला है जो दो अलग-अलग क्षेत्रों - दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया - में अलग-अलग ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र और संस्थागत विरासत के साथ फैला हुआ है। तुलनात्मक विश्लेषण, जैसे कि अनवर (2022) का सार्क और आसियान का अध्ययन, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आसियान बनाम दक्षिण एशियाई संगठनों के अलग-अलग सफलता स्तर भारत के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को आकार देते हैं।

4. अनुसंधान क्रियाविधि

विषय की व्यापक और बहु-विषयक प्रकृति को देखते हुए, यह अध्ययन गुणात्मक साहित्य समीक्षा दृष्टिकोण अपनाता है। यह अकादमिक पत्रिकाओं, नीति पत्रों और विशेषज्ञ विश्लेषणों से प्राप्त निष्कर्षों का संश्लेषण करता है। समीक्षित साहित्य में आर्थिक संपूरकता पर अनुभवजन्य अध्ययन (जैसे चंद्रन 2011), राजनीतिक-सुरक्षा विश्लेषण (अमाडोर एट अल. 2011; किपगेन 2020), और साथ ही आसियान की पहचान और संस्थागत शैली पर वैचारिक कार्य (आचार्य 2009, 2017; नेसादुरई 2008) शामिल हैं। जहाँ तक संभव हो,

विशिष्ट कारकों (जैसे व्यापार आँकड़े, नीतिगत निर्णय) के प्रमाण द्वितीयक स्रोतों से लिए गए हैं। यह अध्ययन द्विपक्षीय मुद्दों (भारत और आसियान के अलग-अलग देश) और एक समूह के रूप में भारत-आसियान सहयोग की परस्पर तुलना करता है, जो संबंधों की बहुस्तरीय प्रकृति को दर्शाता है। विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करके, इस पद्धति का उद्देश्य प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह के बिना एक समग्र समझ विकसित करना है।

5. साहित्य की समीक्षा

राजनीतिक और सुरक्षा कारक:

भारत-आसियान संबंधों के लिए राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी विचार आधारभूत हैं। भारत के हितों में समुद्री सुरक्षा (जैसे हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा), आतंकवाद-रोधी सहयोग और महाशक्तियों के साथ रणनीतिक संतुलन शामिल हैं। इस बीच, आसियान, आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) जैसे आम सहमति-आधारित सुरक्षा ढाँचों पर काम करता है।

अमाडोर एट अल. (2011) ने "आसियान-भारत संबंधों में मुद्दे और चुनौतियाँ: राजनीतिक-सुरक्षा पहलू" का परीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐतिहासिक रूप से, आसियान और भारत के बीच कुछ ही बड़े राजनीतिक-सुरक्षा संघर्ष रहे हैं, लेकिन कुछ मानदंडों पर उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, परमाणु प्रसार और मानवाधिकार नीतिगत भिन्नता के क्षेत्र रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों की आसियान ने आलोचना की थी, हालाँकि आसियान के पास औपचारिक अप्रसार संधि का अभाव है। इसके अतिरिक्त, भारत के लोकतांत्रिक मानदंड इसे मानवाधिकारों पर ज़ोर देने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि आसियान का अहस्तक्षेप का सिद्धांत अक्सर ऐसे मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखता है। अमाडोर एट अल. ने कहा कि इन मतभेदों के बावजूद, "हितों की पारस्परिकता" (आतंकवाद या समुद्री अपराध जैसे साझा सुरक्षा खतरे) संघर्षों को प्रबंधित करने और हल करने के लिए प्रोत्साहन पैदा करती है।

साहित्य संस्थागत मानदंडों की ओर भी इशारा करता है: आसियान का सुरक्षा सहयोग अनौपचारिकता, आम सहमति और अहस्तक्षेप के "आसियान मार्ग" द्वारा निर्देशित होता है। संघर्ष को टालने के लिए प्रशंसित यह दृष्टिकोण संयुक्त कार्रवाई को धीमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एआरएफ (आसियान क्षेत्रीय मंच) आम सहमति से संचालित होता है लेकिन इसकी सीमित प्रभावशीलता के लिए आलोचना की गई है (नारायण 1997)। भारत आसियान के नेतृत्व वाले मंचों (एआरएफ, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन) में भाग लेता है लेकिन, एक गैर-सदस्य होने के नाते, कभी-कभी सूक्ष्म विचलन का सामना करता है: आसियान के सदस्य देश भारत से अपनी गुटनिरपेक्ष शैली के साथ तालमेल बिठाने की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि भारत का अपना सुरक्षा दृष्टिकोण अधिक मुखर हो सकता है। जैसा कि नेसादुरई (2008) ने जोर दिया है, संघर्षों को टालने में "संप्रभुता/हस्तक्षेप न करना और आसियान मार्ग आसियान की सफलता के केंद्र में रहे हैं"।

किपगेन (2020) सुरक्षा आयामों का भी आकलन करते हैं। वे कहते हैं कि आसियान के प्रति भारत का दृष्टिकोण मुख्यतः आर्थिक है, जो बदले में उसकी सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करता है: "हालाँकि, भारत के लिए, यह संबंध किसी भी अन्य मुद्दे की तुलना में आर्थिक सहयोग पर अधिक केंद्रित है"। यह आर्थिक फोकस भारत को दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर टकराव से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है। वास्तव में, किपगेन का तर्क है कि चीन के दक्षिण चीन सागर के दावों को चुनौती देने में भारत की अनिच्छा, दावेदार आसियान देशों को भारत को एक "अविश्वसनीय सुरक्षा साझेदार" के रूप में देखने पर मजबूर करती है। इस प्रकार, चीन-आसियान रणनीतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण बाहरी कारक है: भारत चीन के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को पटरी से उतारे बिना

रणनीतिक संबंध विकसित करना चाहता है, लेकिन यह संतुलनकारी कार्य आसियान देशों को चीनी हठधर्मिता के खिलाफ भारत की समर्थन की इच्छा के बारे में अनिश्चित बना सकता है।

फिर भी, दोनों पक्षों में कुछ रणनीतिक समानताएँ हैं। भारत और आसियान देश आतंकवाद, समुद्री डकैती और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गैर-पारंपरिक खतरों का संयुक्त रूप से सामना करते हैं। मलक्का जलडमरूमध्य में भारतीय नौसैनिक अभ्यास और समुद्री क्षेत्र जागरूकता पर सहयोग इस साझा चिंता को दर्शाते हैं। हालिया साहित्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भी प्रकाश डालता है: भारत समुद्री संचार मार्गों (एसएलओसी) की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आसियान के साथ सहयोग करता है, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इन सुरक्षा साझेदारियों को एआरएफ और एडीएमएम-प्लस (आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस) जैसे मंचों द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिनका भारत सदस्य है, जो संबंधों को मजबूत करने वाले संस्थागत रास्ते प्रदर्शित करते हैं।

संक्षेप में, राजनीतिक-सुरक्षा साहित्य आपसी हितों (आतंकवाद का मुकाबला, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना) और नीतिगत कमियों (मानवाधिकार, चीन-संबंधी सुरक्षा मुद्दे) का मिश्रण दर्शाता है। अमाडोर और अन्य का सुझाव है कि जहाँ "आसियान और भारत एकमत नहीं हैं", वहाँ भी साझा हित संघर्षों को सुलझाने में मदद करते हैं। यह आशावादी दृष्टिकोण इस अवलोकन से कमज़ोर हो जाता है कि भारत अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देता है; जब तक भारत चीन के साथ सीधे टकराव से बचता रहेगा, कुछ आसियान सदस्य भारत की सुरक्षा भूमिका को लेकर सतर्क रहेंगे।

6. आर्थिक और व्यापारिक संबंध

अर्थशास्त्र भारत-आसियान संबंधों की आधारशिला है। वस्तुओं के क्षेत्र में आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) 2010 में और सेवाओं के क्षेत्र में 2014 में लागू हुआ, जो गहन आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। उदारीकरण के बाद से, द्विपक्षीय व्यापार में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है (1990 के दशक में कुछ अरब से बढ़कर 2010 के दशक में अरबों तक)। यह वृद्धि पूरक अर्थव्यवस्थाओं और सक्रिय व्यापार उदारीकरण को दर्शाती है।

चंद्रन (2011) व्यापार अनुकूलता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात का परीक्षण करते हैं कि भारत और आसियान की व्यापार संरचनाएँ किस प्रकार संरेखित हैं, और उत्पाद स्तरों पर सूचकांक (व्यापार तीव्रता सूचकांक, प्रकट तुलनात्मक लाभ) निर्मित करते हैं। उनके निष्कर्ष पूरक क्षेत्रों और उत्पादों को दर्शाते हैं जहाँ प्रत्येक पक्ष तुलनात्मक लाभ रखता है। उदाहरण के लिए, आसियान के इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी क्षेत्र भारत की सेवाओं और कुछ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के पूरक हैं। परिणामस्वरूप, "भारत और आसियान के बीच अधिक सहयोग के लिए पूरक क्षेत्र और उत्पाद उपलब्ध हैं"। यह केवल मुक्त व्यापार समझौते (FTA) द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से आगे भी विकास की संभावना का संकेत देता है।

इससे पहले, सेन एट अल. (2004) (इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली) ने भी इसी तरह मज़बूत व्यापार वृद्धि देखी थी और विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं में मज़बूत पूरकताओं को देखते हुए सकारात्मक संभावनाओं का अनुमान लगाया था। 2010 के बाद के अध्ययन बढ़ते दोतरफ़ा निवेश पर प्रकाश डाल रहे हैं: भारत आसियान के विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे में निवेश करता है, जबकि आसियान कंपनियाँ भारतीय दूरसंचार, ऊर्जा और आईटी में निवेश करती हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, भारत अब जापान जैसी कुछ अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कुछ आसियान देशों (इंडोनेशिया, सिंगापुर) के साथ अधिक व्यापार करता है, जो साझेदारी के आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है।

Copyright@ REST Publisher

हालाँकि, साहित्य आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है। गैर-शुल्क बाधाएँ (एनटीबी), मानकों में अंतर और शुल्क में कमी की असमान गति ने व्यापार की पूर्ण क्षमता को सीमित कर दिया है। उदाहरण के लिए, भारत ने अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए अक्सर उच्च शुल्क बनाए रखा है, जबकि आसियान देशों में कई उत्पादों पर शुल्क कम हैं। कुछ विश्लेषकों (विशेषकर आसियान पर कुरुस 1993) ने तर्क दिया है कि आसियान की आंतरिक आर्थिक सहमति नाजुक हो सकती है। हालाँकि यह सीधे तौर पर भारत के बारे में नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि आसियान पक्ष की वार्ताएँ उसकी आंतरिक राजनीति से प्रभावित हो सकती हैं। भारत की ओर से, सेवा उदारीकरण और योग्यताओं की मान्यता में नौकरशाही की देरी ने सेवा व्यापार को धीमा कर दिया है।

इन अवलोकनों को देखते हुए, आर्थिक कारक संबंधों को प्रभावित करते हैं, सहयोग को सक्षम बनाकर (प्रदर्शित पूरकताओं के माध्यम से) और उसे बाधित करके (संरक्षणवादी उपायों के माध्यम से)। शोधकर्ता आमतौर पर एआईएफटीए और संबंधित पहलों को सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं: ये सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। लेकिन जैसा कि किपजेन (2020) ने लिखा है, भारत अभी भी आर्थिक जुड़ाव को अन्य बातों से ऊपर प्राथमिकता देता है, जिसका अर्थ है कि आर्थिक साधन साझेदारी का मुख्य आधार बने रहने की संभावना है।

7. सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध

सांस्कृतिक आत्मीयता और लोगों के बीच संपर्क भारत-आसियान संबंधों में एक सूक्ष्म, किन्तु महत्वपूर्ण, कारक हैं। ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं: प्राचीन दक्षिण-पूर्व एशियाई साम्राज्य भारतीय संस्कृति, धर्म (हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म) और भाषा से गहराई से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, बौद्ध संबंधों और भारतीय महाकाव्यों (रामायण, महाभारत) के प्रसार ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में साझा सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया है। आधुनिक समय में, यह साझा विरासत सद्भावना और सौम्य शक्ति को बढ़ावा देती है। भारत और आसियान दोनों ने "सभ्यतागत" संबंधों को मज़बूत साझेदारी के आधार के रूप में सराहा है।

समकालीन सांस्कृतिक कूटनीति में शिक्षा, कला और पर्यटन के क्षेत्र में आदान-प्रदान शामिल है। आसियान-भारत "सांस्कृतिक सहयोग" ढाँचा (जैसे, अलग-अलग सदस्य देशों के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन) इन संबंधों के लिए संस्थागत समर्थन को दर्शाता है। हालाँकि अकादमिक रूप से इस पर उतना व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी इस तरह के आदान-प्रदान से परिचय और आपसी समझ का निर्माण होता है। किपगेन (2020) सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को संबंधों के एक स्तंभ के रूप में स्वीकार करते हैं (हालाँकि वे उन्हें आर्थिक और राजनीतिक आयामों के मुकाबले गौण मानते हैं)।

इसके अलावा, प्रवासी समुदाय (जैसे मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय मूल के लोग) और व्यावसायिक संबंध समाजों को जोड़ने में योगदान करते हैं। हालाँकि साहित्य में अक्सर अर्थशास्त्र और सुरक्षा पर ज़ोर दिया जाता है, आसियान-भारत केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि "सांस्कृतिक सहयोग" भारत के अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मज़बूत सांस्कृतिक संबंध राजनीतिक मतभेदों को कम कर सकते हैं; उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक सहानुभूति के कारण आसियान के सदस्य देश भारत के साथ साझेदारी के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। इसके विपरीत, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव की कमी एक चूका हुआ अवसर हो सकता है: कुछ अध्ययन दीर्घकालिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए युवाओं के बीच अधिक आदान-प्रदान और शैक्षिक सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

कुल मिलाकर, सांस्कृतिक कारक संबंधों में एक सेतु का काम करते हैं। ये कारक एशियाई अंतर्संबंधों के व्यापक आख्यान को पुष्ट करते हैं। पारंपरिक सभ्यतागत संबंधों का अर्थ है कि भारत और आसियान एक क्षेत्रीय सभ्यतागत स्थान साझा करते हैं, जिससे यूरोप-एशिया

संबंधों जैसे "अन्यता" को कम किया जा सकता है। साझी विरासत का जश्न मनाकर, दोनों पक्ष अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।

8. संस्थागत और क्षेत्रीय ढांचा

संस्थागत कारक इस बात से संबंधित हैं कि भारत एक संगठन के रूप में आसियान के साथ किस प्रकार जुड़ता है और दोनों पक्षों के शासन संबंधी मानदंड कितने सुसंगत हैं। आसियान को उसके क्षेत्रीय ढाँचों (आसियान सचिवालय, विभिन्न परिषदें और समितियाँ, और आसियान चार्टर) द्वारा परिभाषित किया जाता है जो आम सहमति, संप्रभुता और क्रमिक दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हैं। इसके विपरीत, भारत, औपचारिक सदस्य के रूप में आसियान में शामिल होने के बजाय, अक्सर द्विपक्षीय रूप से या व्यापक समूहों (जैसे बिम्सटेक या प्रस्तावित आईओआरए ढाँचे) के भीतर मुद्दों पर विचार करता है।

एक प्रमुख संस्थागत अंतर निर्णय लेने की शैली में निहित है। नेसादुरई (2008) द्वारा अध्ययन किए गए "आसियान मार्ग" में अनौपचारिक, आम सहमति-आधारित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आसियान देश परामर्श और सर्वसम्मत समझौते बनाने के आदी हैं; वे बाध्यकारी प्रवर्तन से बचते हैं। भारत की शैली, जो कभी-कभी बहुपक्षवाद का पक्षधर भी है, उस विशिष्ट विरासत से जुड़ी नहीं है। यह बेमेल सहयोगात्मक परियोजनाओं की गति को धीमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत-आसियान संवाद अक्सर ऐसे संयुक्त वक्तव्यों में परिणत होते हैं जो बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के बजाय सभी को संतुष्ट करने के लिए अनिवार्य रूप से अस्पष्ट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत आसियान के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सकता है, लेकिन पहलों (जैसे साइबर सुरक्षा या पर्यावरण सहयोग) पर प्रगति कुछ द्विपक्षीय विकल्पों की तुलना में धीमी हो सकती है।

शैली के अलावा, संस्थागत स्तर पर जुड़ाव भी एक कारक है। भारत आसियान के नेतृत्व वाले मंचों (जैसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एआरएफ, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस) में भाग लेता है जिससे एजेंडा व्यापक होता है। ये संस्थाएँ सुरक्षा संवाद के लिए मंच प्रदान करती हैं, लेकिन ये बहुपक्षीय और आम सहमति से प्रेरित हैं, इसलिए भारत किसी एक मुद्दे को एकतरफा नहीं उठा सकता। व्यापार और अर्थशास्त्र के संदर्भ में, आसियान का अपना आंतरिक एकीकरण (आसियान आर्थिक समुदाय) भारत के लिए एक "आसियान बाज़ार" बनाता है, लेकिन इसके लिए भारत को आसियान-व्यापी नियमों (उदाहरण के लिए, मुक्त व्यापार समझौते में उत्पत्ति के नियमों) के साथ तालमेल बिठाने की भी आवश्यकता होती है। भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच कानूनी और नियामक व्यवस्थाओं में अंतर कभी-कभी समझौतों के कार्यान्वयन को जटिल बना देता है।

तुलनात्मक क्षेत्रवाद छात्रवृत्ति (रूलैंड 2001; आचार्य 2017) अक्सर सार्क में भारत की भूमिका (या यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों) के साथ आसियान के संस्थागत मॉडल की तुलना करती है। ये विश्लेषण बताते हैं कि आसियान की अपेक्षाकृत मजबूत संस्थागत एकजुटता (इसकी सीमाओं के बावजूद) कमजोर दक्षिण एशियाई ढांचे (सार्क) के विपरीत है, जो आसियान को भारत के लिए अधिक आकर्षक भागीदार बनाती है। वास्तव में, अनवर (2022) ने सार्क की तुलना में आसियान के तेजी से व्यापार विकास और उच्च उपलब्धियों पर ध्यान दिया है। निहितार्थ यह है कि भारत आसियान की संस्थाओं को अधिक प्रभावी और स्थिर मानता है, जो जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, आसियान की अपनी सीमाओं (जैसे सदस्य विवादों में हस्तक्षेप करने में असमर्थता) का यह भी अर्थ है कि भारत द्विपक्षीय मुद्दों (जैसे बांग्लादेश के साथ भारत की समुद्री सीमा

नेसादुरई (2008) और आचार्य (2017) भी पहचान और मानदंडों का मुद्दा उठाते हैं। आसियान की पहचान "सामाजिक और राजनीतिक रूप से निर्मित" है और इसे कभी भी पूर्व-निर्धारित नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि आसियान का चरित्र उसके सदस्यों और उनके फैसलों से आकार लेता है। भारत, एक अलग क्षेत्रीय पहचान (दक्षिण एशियाई, अपने स्वयं के इतिहास के साथ) से आने के कारण,

कभी-कभी अलग-अलग अपेक्षाएं रख सकता है। साहित्य बताता है कि दोनों पक्ष इन मतभेदों से अवगत हैं: आसियान देश भारत से आसियान के तरीके का सम्मान करने की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि भारत कभी-कभी आम सहमति की बाधाओं से परेशान हो सकता है। हालांकि, संस्थागत नवाचार के लिए जगह है: उदाहरण के लिए, आसियान-भारत वार्षिक शिखर बैठकें और क्षेत्रीय संवाद साझेदारी (संस्कृति से लेकर कृषि तक के क्षेत्रों को कवर करती हैं) सहयोग के लिए संस्थागत मंच बन गए हैं।

संबंधों को प्रभावित करने वाला एक संस्थागत कारक सदस्य देशों के भीतर की घरेलू राजनीति है। आसियान में विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं (लोकतंत्र, राजतंत्र, सैन्य शासन) वाले देश शामिल हैं। एक लोकतंत्र के रूप में, भारत कभी-कभी लोकतांत्रिक आसियान सदस्यों के साथ समान हित खोज लेता है, लेकिन गैर-लोकतांत्रिक सदस्यों की आलोचना करने में भी सावधानी बरत सकता है (आसियान के मानदंडों का सम्मान करने के लिए)। इसके विपरीत, गैर-लोकतांत्रिक आसियान देश राजनीतिक शासन के लेबल के बिना भारत की सरकार-से-सरकार कूटनीति से निपटना पसंद कर सकते हैं। यह परस्पर क्रिया राजनीतिक-सुरक्षा क्षेत्रों (जैसे मानवाधिकार, शासन संवाद) में विश्वास और सहयोग की गति को प्रभावित करती है।

कुल मिलाकर, संस्थागत कारक - आसियान का सर्वसम्मति से संचालित ढाँचा, भारत की द्विपक्षीयता, और क्षेत्रीय संस्थाओं में अंतर्निहितता का स्तर - यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या हासिल किया जा सकता है। ये कारक जुड़ाव की गति और गहराई को प्रभावित करते हैं: साझा संस्थाएँ अवसर तो प्रदान करती हैं, लेकिन भारत-आसियान परियोजनाओं पर बाधाएँ भी डालती हैं।

9. भू-राजनीतिक संदर्भ और बाहरी प्रभाव

हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण कारक चीन का उदय और एशिया में महाशक्ति की बदलती गतिशीलता रही है। चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख सुरक्षा अभिनेता है (अपने समुद्री दावों, बेल्ट एंड रोड निवेश आदि के माध्यम से)। भारत आसियान को आंशिक रूप से चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा के लेंस के माध्यम से देखता है। इस प्रकार भारत-आसियान साझेदारी भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ जुड़ गई है, जहां आसियान की केंद्रीयता एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। हालांकि, जैसा कि किपगेन (2020) और अन्य ने नोट किया है, चीन के मुद्दों पर भारत की सापेक्ष मितव्ययिता आसियान द्वारा देखी गई है। यदि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की कार्रवाइयों का प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो आसियान देश (विशेषकर वियतनाम या फिलीपींस जैसे दावेदार) भारत को एक मजबूत सुरक्षा सहयोगी के रूप में नहीं देख सकते हैं।

एक अन्य बाहरी प्रभाव अन्य शक्तियों की भूमिका है: संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक साझेदार रहा है, और आसियान के सदस्य देश कभी-कभी चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका या जापान के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। आसियान, भारत के आसियान के साथ संबंधों को इस आधार पर भी देखता है कि वह इन शक्तियों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अभ्यास (जैसे भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय, या भारत-आसियान नौसैनिक अभ्यास) बहुपक्षीय आयाम बनाते हैं।

वैश्विक आर्थिक रुझान और संकट भी संबंधों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, 2008 के वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी ने व्यापारिक संबंधों के लचीलेपन की परीक्षा ली। भारत और आसियान दोनों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश की है (जैसे, भारत को चीन के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखना) - एक ऐसा कारक जो आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। इसके विपरीत, किसी भी साझेदार की संरक्षणवादी या अंतर्मुखी नीतियाँ साझेदारी को प्रभावित कर सकती हैं। हालाँकि, अब तक, किसी भी

पक्ष ने नीति के रूप में खुले व्यापार से कोई खास पीछे हटने का फैसला नहीं किया है, न ही दोनों बड़े व्यापारिक समूहों (जैसे, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, हालाँकि भारत 2019 में चिंताओं के कारण आरसीईपी से हट गया था) के सदस्य हैं।

अंत में, म्यांमार के राजनीतिक संकट जैसे भू-राजनीतिक घटनाक्रम चुनौतियाँ पेश करते हैं: आसियान को म्यांमार के तख्तापलट से निपटने में संघर्ष करना पड़ा है, और भारत (जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है) की अपनी चिंताएँ हैं। ऐसे क्षेत्रीय संघर्ष या तो आसियान और भारत को (अपने पड़ोस को स्थिर करने के लिए) और अधिक सहयोग करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या अगर उनकी प्राथमिकताएँ अलग-अलग हों तो मतभेद पैदा कर सकते हैं।

10. हालिया घटनाक्रम (एक्ट ईस्ट नीति, क्षेत्रीय पहल)

2010 और 2020 के दशकों में, भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के माध्यम से आसियान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। यह अधिक शिखर सम्मेलनों, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (जैसे भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) और संपर्क पहलों (जैसे, म्यांमार में बंदरगाह विकास) में परिलक्षित हुआ है। आसियान-भारत कार रैली और पर्यटन में वृद्धि जैसे कार्यों का उद्देश्य लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना है। ये ठोस कदम आम तौर पर संबंधों को मजबूत करते हैं, लेकिन उनकी सफलता वित्त पोषण और कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, जो बदले में राजनीतिक इच्छाशक्ति और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि एक्ट ईस्ट पर ज़ोर ने आसियान को भारत की रणनीति के केंद्र में रखा है, यहाँ तक कि कुछ आसियान देशों (जैसे बांग्लादेश, म्यांमार) में घरेलू चुनौतियों के बावजूद भी।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा सहयोग नए क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है: आतंकवाद (आसियान ने आतंकवादी हमलों का सामना किया है) और डिजिटल तकनीक (साइबर सुरक्षा) पर चर्चाएँ संवाद का हिस्सा बन रही हैं। उदाहरण के लिए, चरमपंथी उग्रवाद पर साझा चिंता ने आसियान और भारत को संयुक्त कार्यशालाओं और पुलिस आदान-प्रदान के लिए एक साथ लाया है। इसी प्रकार, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन भी एजेंडे में शामिल हो गए हैं, जो वैश्विक रुझानों और एक सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय के निर्माण में आसियान की रुचि, दोनों को दर्शाता है।

हालाँकि, हाल के वर्षों में कुछ ठहराव भी देखा गया है। 2019-2020 के आसपास (कोविड-19 से पहले भी) व्यापार वृद्धि स्थिर रही। कुछ विश्लेषक आगाह करते हैं कि आगे उदारीकरण या नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के दौर के बिना, आर्थिक संबंध स्थिर हो सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से, म्यांमार में मानवीय संकट एक नई चुनौती पैदा करता है: आसियान के सर्वसम्मत दृष्टिकोण की परीक्षा हो चुकी है, और भारत को अपने एक्ट ईस्ट लक्ष्यों को व्यावहारिक चिंताओं (शरणार्थियों, सीमा स्थिरता) के साथ संतुलित करना होगा। ये घटनाक्रम संकेत देते हैं कि भारत-आसियान संबंधों का विकास तो हो रहा है, लेकिन यह वर्तमान घटनाओं और घरेलू राजनीति के प्रति संवेदनशील है।

11. निष्कर्ष

भारत-आसियान साझेदारी कारकों के एक जटिल अंतर्क्रिया द्वारा आकार लेती है। आर्थिक रूप से, दोनों पक्षों में मजबूत पूरकताएँ हैं जिन्होंने व्यापार और निवेश में उछाल को प्रेरित किया है; व्यापार समझौतों के माध्यम से इसे संस्थागत रूप देना काफी हद तक सफल रहा है, हालाँकि कुछ गैर-टैरिफ बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से, क्षेत्रीय स्थिरता और गैर-पारंपरिक सुरक्षा (जैसे आतंकवाद-निरोध, समुद्री सुरक्षा) में साझा हित सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन चीन की भूमिका और संप्रभुता के मानदंडों जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से, गहरे ऐतिहासिक संबंध एक अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जबकि

आधुनिक लोगों से लोगों का आदान-प्रदान आपसी सद्भावना को बनाए रखने में मदद करता है। संस्थागत रूप से, आसियान की आम सहमति पर आधारित शैली (स्थापित आसियान+भारत मंचों के माध्यम से) जुड़ाव को सुगम बनाती है और इसे बाधित भी करती है (भारत से धैर्य और अहस्तक्षेप की मांग करती है)। अंत में, बाहरी कारक - विशेष रूप से चीन का प्रभाव और एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत की अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएँ - साझेदारी को काफी हद तक प्रभावित करती हैं।

कुल मिलाकर, हालिया शोध आशावादी हैं: पारस्परिक लाभों को देखते हुए, संघर्षों को प्रबंधित किया जा सकता है। अमाडोर एट अल. (2011) का निष्कर्ष है कि साझा हितों के कारण "संभावित संघर्षों को सुलझाया जा सकता है"। किपजेन (2020) तो संबंधों में निरंतर वृद्धि की भविष्यवाणी भी करते हैं, विशेष रूप से आर्थिक कारणों से। इस क्षमता को अधिकतम करने के लिए, भारत और आसियान दोनों को विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है: भारत समान विचारधारा वाले आसियान सदस्यों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर अधिक आत्मविश्वास से जुड़ सकता है, और आसियान भारत के साथ मिलकर अपनी निर्णय प्रक्रियाओं को यथासंभव अधिक कार्य-उन्मुख बनाने के लिए काम कर सकता है। सांस्कृतिक और संस्थागत संबंधों को मजबूत करना (जैसे शिक्षा आदान-प्रदान या थिंक-टैंक संवादों के माध्यम से) भी साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

संक्षेप में, भारत-आसियान संबंध बहुआयामी हैं, और प्रत्येक कारक - चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या संस्थागत हो - इसके प्रक्षेप पथ को प्रभावित करता है। एक समग्र दृष्टिकोण जो पूरकताओं (जैसे व्यापार) का लाभ उठाता है और मतभेदों (जैसे नीतिगत मतभेद) का प्रबंधन करता है, साहित्य द्वारा समर्थित मार्ग प्रतीत होता है। दोनों पक्षों द्वारा नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था और संवाद तंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, संबंधों के और प्रगाढ़ होने की संभावना है, हालाँकि इसकी चुनौतियों का सावधानीपूर्वक समाधान किए बिना नहीं।

संदर्भ

[1]. आचार्य, ए. (2009). आसियान के बारे में बहस: हम किस बात पर असहमत हैं? कैम्ब्रिज रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 22(3), 493–499.

[2]. आचार्य, ए. (2017). आसियान पहचान का विकास और सीमाएँ। आसियान@50: आसियान समुदाय का निर्माण - राजनीतिक-सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन (खंड 4, पृष्ठ 25-42) में। जकार्ता: आसियान सचिवालय।

[3]. अमाडोर, जेएस, पेनालबर, एएल, और बोबिलो, एएस (2011)। आसियान-भारत संबंधों में मुद्दे और चुनौतियाँ: राजनीतिक-सुरक्षा पहलू। इंडिया क्वार्टरली: ए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 67(2), 111–127।

[4]. अनवर, एम.एफ. (2022). सार्क और आसियान: एक तुलनात्मक अध्ययन सफलता और विफलता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 11(2), 13–23.

[5]. चंद्रन, एस. (2011). भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार अनुकूलता (एसएसआरएन स्कॉलरली पेपर संख्या आईडी 1932266). सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क. https://doi.org/10.2139/ssrn.1932266

[6]. किपगेन, एन. (2020). भारत-आसियान संबंध: पहल, सफलताएँ और चुनौतियाँ. इंडिया रिव्यू, 19(3), 207–222.

[7]. नेसादुरई, एचईएस (2008)। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)। न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी, 13(2), 225–239।

[8]. योंग, टीटी, और सी, सीएम (2009)। भारत-आसियान संबंधों का विकास। इंडिया रिव्यू, 8(1), 20–42।

[9]. आसियान-भारत केंद्र (2022)। एआईसी टिप्पणी: आसियान-भारत संबंध। आरआईएस में आसियान-भारत केंद्र। https://www.aseanindiacentre.org.in/sites/default/files/2022-05/AIC%20commentary%20April%202022.pdf